हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय स्वाभिमान

RNI No. : MAHHIN/2008/24084.   www.rashtriyaswabhimaan.com

वर्ष : 17   अंक : 106   मुंबई, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025   पृष्ठ : 4   मूल्य 1 रुपए

खबर संक्षेप

मुंबई में ई-चालान की नई नीति पर काम शुरू, फडणवीस ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर विधान परिषद में बुधवार को कहा कि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए ई-चालान जारी करने की नई और आधुनिक नीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति में नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और विभिन्न राज्यों और देशों में अपनाई गई प्रभावी पद्धतियों का अध्ययन किया जाएगा, ताकि चालक और यातायात नियंत्रण दोनों के लिए प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाई जा सके।

फडणवीस ने इस दिशा में वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में एक अध्ययन समूह गठित करने की घोषणा की। इस समूह का मुख्य उद्देश्य दोपहिया वाहनों और पार्किंग संबंधी समस्याओं समेत पूरे शहर के यातायात नियोजन की समीक्षा करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह ई-चालान प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के साथ-साथ इसके निष्पक्ष और नियंत्रित संचालन पर भी ध्यान देगा। सदस्य सुनील शिंदे के प्रश्न पर राज्यमंत्री योगेश कदम ने स्पष्ट किया कि हवालदारों को निजी मोबाइल फोन से फोटो लेकर ई-चालान जारी करने की अनुमति नहीं होगी। इसके बजाय उन्हें विशेष कैमरे और तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे चालान प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और नियंत्रित हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लंबित दंड की वसूली में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए लोक अदालत और अमनेस्टी योजना के माध्यम से अब 50 प्रतिशत तक दंड की वसूली की जाएगी।

भविष्य की योजनाओं का भी संकेत देते हुए फडणवीस ने कहा कि जल्द ही दंड की राशि को फास्टैग प्रणाली से सीधे जोड़े जाने की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। इससे वाहन चालकों को तुरंत संदेश प्राप्त होगा और प्रक्रिया अधिक सुलभ, तेज और पारदर्शी बनेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-चालान प्रणाली को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएँ और इसमें किसी भी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा नहीं आए।

इस पहल का उद्देश्य न केवल यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, बल्कि शहर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और वाहनों के बढ़ते दबाव के बावजूद शहर के यातायात प्रवाह को सुचारू बनाना भी है। अधिकारियों का मानना है कि इस नई नीति के लागू होने के बाद मुंबई में सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियंत्रण और अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।

असम में शहीद स्मारक का उद्‌घाटन, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने नागरिकों को सतर्क रहने की दी चेतावनी

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को बोरागाँव में असम आंदोलन के शहीद दिवस के अवसर पर भव्य शहीद स्मारक का उद्‌घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नागरिकों से विशेष आग्रह किया कि वे अज्ञात लोगों से दूरी बनाएं, किसी अनजान व्यक्ति को नौकरी न दें, अपनी जमीन न बेचें और खेती के लिए अजनबी व्यक्तियों को न लाएं। उनका यह संदेश राज्य में सुरक्षा और सतर्कता बनाए रखने के महत्व पर केंद्रित था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्मारक उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने 1979 में बांग्लादेश से घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाई और असम के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। स्मारक का निर्माण पश्चिम बोरागाँव में 150 बीघा से अधिक भूमि पर किया गया है और इसकी कुल लागत 170 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि स्मारक के परिसर में 500 सीटों वाला सभागार और डिजिटल पुस्तकालय भी बनाया जाएगा, जिसमें असम आंदोलन और असमिया इतिहास की 5000 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री अतुल बोरा, केशव महंत, बिमल बोरा, पीयूष हजारिका, जयंत मल्लबारुआ, मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा, वरिष्ठ अधिकारी और एएएसयू के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक का उद्‌घाटन कर इसे राज्यवासियों के लिए स्मरण और प्रेरणा का स्थल बताते हुए कहा कि यह आने वाली पीढ़ियों को असम के संघर्ष, उसकी पहचान और इतिहास से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम होगा। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि स्मारक केवल एक भव्य संरचना नहीं है, बल्कि यह असम के युवाओं को जागरूक करने और उन्हें अपने सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास से जोड़ने का एक प्रयास है।

महाराष्ट्र में गुटखा, घटिया दवा और शराब नीति को लेकर सख्त कार्रवाई, मुख्यमंत्री और मंत्री ने उठाए अहम कदम

मुंबई। महाराष्ट्र में गुटखा कारोबारियों, घटिया दवाओं और शराब की दुकानों को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में गुटखा बनाने और बेचने वाले अपराधियों के खिलाफ मकोका लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गुटखा कारोबारियों की आपराधिक चेन को तोड़ने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एफडीए की कार्रवाई के बावजूद राज्य में गैरकानूनी तरीके से बड़ी मात्रा में गुटखा और खुशबूदार सुपारी लाई जाती है, जिसे रोकना अब आसान होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मकोका लागू होने से एफडीए की कार्रवाई को मजबूती मिलेगी और इस आपराधिक चेन को खत्म करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों के आसपास गुटखा और पान मसाले की अवैध बिक्री पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी और जहां भी उल्लंघन होगा, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गुटखा और नशीले पदार्थों के खिलाफ प्रभावी कानून बनाने के लिए विधि और न्याय विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा ताकि मकोका के दायरे में सभी गुटखा कारोबारियों को लाया जा सके।

इसी क्रम में, राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री नरहरि झिरवल ने विधानसभा में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पिछले एक वर्ष में घटिया और निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं की बिक्री करने वाले 215 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इनमें 176 खुदरा और 39 थोक विक्रेता शामिल हैं। इसके अलावा, 136 खुदरा और 93 थोक विक्रेताओं का गहन निरीक्षण किया गया और आवश्यक कार्रवाई की गई। मंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2024 में एफडीए अभियान के दौरान मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद और नागपुर में कुल 36 दवा नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा गया, जिनमें से 34 दवाएं निम्न गुणवत्ता की पाई गईं। इन दवाओं में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, तपेदिक, हृदय रोग और रक्त शुद्ध करने वाली दवाएं शामिल थीं। मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और घटिया दवाओं की बिक्री रोकने के लिए आवश्यक थी।

साथ ही, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में घोषणा की कि अब राज्य में शराब की दुकानें खोलना आसान नहीं रहेगा। चाहे यह इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) बेच रही हों या देसी शराब, किसी भी शराब दुकान को अपनी जगह पर काम शुरू करने से पहले संबंधित हाउसिंग सोसाइटी से अनिवार्य मंजूरी लेनी होगी। उपमुख्यमंत्री ने यह पॉलिसी पूरे महाराष्ट्र में समान रूप से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह कदम हाउसिंग सोसाइटी और आसपास के निवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है और इस नीति से शराब दुकानों के संचालन में पारदर्शिता आएगी।

राज्य सरकार की ये कार्रवाइयां गुटखा और नशीले पदार्थों की बिक्री, घटिया दवाओं और शराब नीति को लेकर सख्त कदम उठाने के रूप में देखी जा रही हैं। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और एफडीए मंत्री की ओर से की गई ये घोषणाएं न केवल कानून और नियमों की सख्ती को दर्शाती हैं, बल्कि राज्य में लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट करती हैं।

लाडकी बहिण योजना पर खुला सबसे बड़ा पर्दाफाश, 21 करोड़ की हेराफेरी से सदन में हड़कंप, सरकार ने दोषियों से पूरी रिकवरी का दिया भरोसा

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे के एक विवादास्पद भूमि सौदे की पुलिस जांच पर बुधवार को कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल उठाए कि क्या अधिकारी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को प्राथमिकी में नामजद न करके उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायमूर्ति माधव जामदार की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस मामले में आरोपी व्यवसायी शीतल तेजवानी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष से तीखे सवाल पूछे। न्यायधीश ने यह ध्यान दिलाया कि अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी नामक कंपनी में अधिकतम साझेदारी पार्थ पवार के पास है, इसके बावजूद उनका नाम प्राथमिकी में शामिल नहीं किया गया। न्यायमूर्ति जामदार ने सीधे सवाल किया कि क्या पुलिस केवल अन्य आरोपियों की जांच कर रही है और पार्थ पवार को बचा रही है।

इस पर लोक अभियोजक मनकुंवर देशमुख ने जवाब दिया कि मामले की जांच कर रही पुलिस कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगी और किसी के साथ विशेष व्यवहार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया और स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

मामला पुणे के पॉश मुंधवा इलाके में स्थित 40 एकड़ जमीन के विवाद से जुड़ा है। यह जमीन सरकारी संपत्ति थी, जिसे बेचने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद इसे 300 करोड़ रुपये में अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को बेचा गया, जिसमें पार्थ पवार की हिस्सेदारी बताई जाती है। आरोप है कि इस कंपनी को 21 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी से भी छूट मिली। संयुक्त पंजीकरण महानिरीक्षक की अध्यक्षता वाली समिति ने कारोबारी दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी और उप-पंजीयक रविंद्र तारू को जिम्मेदार ठहराया और इन्हें FIR में नामजद किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि पार्थ पवार का नाम FIR में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क पर संदेह जताते हुए पूछा कि क्या उनकी हिस्सेदारी और भूमिका की पूरी तरह जांच की गई है। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी आरोपियों पर समान रूप से लागू हो, ताकि किसी भी राजनीतिक दबाव या संरक्षण का प्रभाव न पड़े।

महाराष्ट्र में जिला परिषद और महापालिका चुनाव में महायुति का एकजुट मोर्चा, फडणवीस-बावनकुले ने की बड़ी घोषणा

नागपुर। महाराष्ट्र में आगामी जिला परिषद और महानगरपालिका चुनावों को लेकर महायुति एकजुट होकर मैदान में उतरेगी और इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले करेंगे। बावनकुले ने स्पष्ट किया कि महायुति का लक्ष्य कुल 51 प्रतिशत मत हासिल करना है और इस चुनाव में गठबंधन सभी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव हम साथ मिलकर ही लड़ेंगे और इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी घोषणा की कि महायुति मिलकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भाग लेगी। फडणवीस ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी की चर्चाओं के बावजूद हमारा गठबंधन 2029 के चुनाव में भी कायम रहेगा। मुंबई महानगरपालिका चुनाव की तैयारियों में भी तेजी आ गई है। बावनकुले ने बताया कि सीट बंटवारे के लिए भाजपा और शिवसेना के चार-चार प्रतिनिधि और महायुति के सदस्य मिलकर समन्वय समिति बनाएंगे। इस समिति का उद्देश्य विवादित सीटों पर चर्चा कर निष्पक्ष और रणनीतिक निर्णय लेना होगा। वहीं मुंबई के मेयर पद के लिए अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की संयुक्त बैठक में लिया जाएगा।

स्थानीय स्तर पर कुछ मतभेद होने की संभावना को बावनकुले ने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 5 से 10 प्रतिशत सीटों को लेकर विवाद होने पर अंतिम निर्णय फडणवीस और शिंदे खुद करेंगे, जिससे महायुति की एकजुटता बनी रहे। उन्होंने जिला स्तर के नेताओं को भी निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर महायुति का मजबूत ढांचा तैयार करें और सभी मतभेदों को हल करने का प्रयास करें। बावनकुले ने यह भी पुष्टि की कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार महायुति का अभिन्न हिस्सा हैं और आने वाले चुनाव में पूरी तरह गठबंधन के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार कुछ चुनाव संबंधित मतभेद कार्यकर्ताओं के बीच उत्पन्न हुए थे, लेकिन अब वह पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। बावनकुले ने यह भी जोर दिया कि हमारे बीच मनभेद कभी नहीं थे, केवल चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे को लेकर असहमति थी, जिसे अब शीर्ष नेतृत्व द्वारा समाधान कर दिया गया है।

महायुति का यह एकजुट मोर्चा राज्य में चुनावी माहौल को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व में गठबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सीटों पर रणनीति प्रभावी और निष्पक्ष रूप से लागू हो, जिससे राज्य में महायुति की मजबूत उपस्थिति और जीत की संभावना बढ़ सके। इस तरह महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय चुनाव महायुति की एकजुट ताकत और रणनीतिक योजना का असली परीक्षण बनने जा रहा है।

मुंबई में फर्जी जन्म प्रमाणपत्र रैकेट का भंडाफोड़, 367 लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे कर रहे थे आवेदन

मुंबई। मुंबई में फर्जी दस्तावेजों के सहारे जन्म प्रमाणपत्र जारी कराने का बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसने प्रशासन और नागरिकों में चिंता की लहर दौड़ा दी है। मुलुंड पुलिस स्टेशन ने नजमा खातून, अशरफ अखबर खान, मोहम्मद औसफ सिद्दीकी, गौसिया परवीन शेख समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जन्म प्रमाणपत्र न केवल पहचान का अहम दस्तावेज है बल्कि नागरिकता से जुड़ा भी महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, इसलिए इस घोटाले के खुलासे ने प्रशासन में सनसनी मचा दी है।

पुलिस के अनुसार आरोपी अलग-अलग फर्जी और जाली दस्तावेजों का उपयोग कर जन्म प्रमाणपत्र हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। जांच में पाया गया कि इन दस्तावेजों में नाम, पता और अन्य महत्वपूर्ण विवरण गढ़े हुए थे। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं 336(3), 340(2), 318(4) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा जन्म पंजीकरण अधिनियम की धारा 23 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में गलत जानकारी देना और जालसाजी जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं।

पूर्व सांसद और भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस घोटाले का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कुल 367 लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाणपत्र लेने का प्रयास किया। सोमैया ने यह भी दावा किया कि यह गिरोह केवल मुंबई तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य राज्यों में भी सक्रिय है। उनका कहना है कि इस तरह के फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए लोग भविष्य में नागरिकता और सरकारी लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं।

पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों ने संबंधित दस्तावेजों और आवेदन पत्रों की पड़ताल शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी अलग-अलग नाम, पते और प्रमाणों का सहारा लेकर जन्म प्रमाणपत्र बनवाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा पुलिस ने संबंधित नगरपालिका और सरकारी विभागों से रिकॉर्ड तलब किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए किसी को नागरिक अधिकारों या सरकारी सुविधाओं का लाभ न मिल सके।

इस खुलासे के बाद प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस प्रकार की जालसाजी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे।

जहरीला कफ सिरप कांड : यूपी में जहरीली दवाओं पर कब लगेगी लगाम, सिस्टम की नाकामी पर सवाल

क्या योगी सरकार भाजपा से जुड़े लोगों को बचाने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को बना रही है निशाना?

मुंबई। उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप की अवैध तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा होने के बाद दवा नियमन, लाइसेंसिंग और कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। करोड़ों रुपये की कफ सिरप की खेप, फर्जी लाइसेंस और सीमा पार नेटवर्क ने साफ कर दिया है कि दवाइयों की निगरानी व्यवस्था में गंभीर खामियां मौजूद हैं। सरगना अंबरीश को बचाने के लिए शुभम जायसवाल पर कसा शिकंजा, पिता समेत कईयों को गिरफ्तार किया। शुभम जायसवाल को इस रैकेट का मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है। उसके कई सहयोगियों और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शुभम के खिलाफ विदेश (यूएई) से प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने विभिन्न जिलों में लगातार छापेमारी कर नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश तेज कर दी है।

ड्रग रेगुलेशन पर उठे सवाल

कफ सिरप स्कैंडल ने राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर ड्रग रेगुलेशन की कमजोरियों को उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लाइसेंसिंग, निरीक्षण और ऑनलाइन दवा ट्रैकिंग सिस्टम प्रभावी होते, तो जहरीली दवाओं की इतनी बड़ी खेप बाजार और तस्करी नेटवर्क तक नहीं पहुंच सकती थी।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप ने बढ़ाया विवाद

मामला सामने आने के बाद इसका राजनीतिक पहलू भी गर्म हो गया है। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े अंबरीश सिंह भोला ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी पर मानहानि का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि दोनों ने कफ सिरप मामले में उनका नाम गलत तरीके से घसीटा। मामला फिलहाल न्यायालय और जांच एजेंसियों के दायरे में है।

FSDA व पुलिस की जांच जारी, बड़ी कार्रवाई की मांग

FSDA, पुलिस और अन्य एजेंसियां दवा कंपनियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेडिकल स्टोर्स की भूमिका खंगाल रही हैं। विपक्ष और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि जब तक लाइसेंसिंग अधिकारियों व संभावित राजनीतिक संरक्षण की जांच नहीं होगी, तब तक असली गुनहगारों तक पहुंचना संभव नहीं है।

पीड़ित परिवारों का दर्द, न्याय और मुआवजे की मांग

जहरीले कफ सिरप से हुई संदिग्ध मौतों और बीमारियों से प्रभावित परिवार न्याय, मुआवजा और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जनता का सवाल है कि जब दवा ही ज़हर बन जाए तो आम आदमी किस पर भरोसा करे। सुरक्षित और सस्ती दवाएं नागरिकों का बुनियादी अधिकार हैं, ऐसे में सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग तेज हो रही है।

संपादकीय

धनी देशों की तंगदिली से बढ़ेगी मृत्यु दर

इस सदी के ढाई दशक में बाल मृत्यु दर घटने को दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया गया था, लेकिन अब इस सदी में पहली बार बाल मृत्यु दर में वृद्धि की आशंका जतायी जा रही है। गेट्स फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है दुनिया भले ही अमीर हो गई है लेकिन गरीब देशों के बच्चों पर होने वाला खर्च घटा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, धनी देशों द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य खर्च पर 27 फीसदी की कटौती की गई है। जिससे इस वर्ष दो लाख अतिरिक्त बच्चों की मौत की आशंका जतायी जा रही है। दरअसल, ये मौतें उन बीमारियों से हो सकती हैं, जिन्हें अमीर देशों से मिलने वाली मदद से होने वाले टीकाकरण और बुनियादी इलाज से टाला जा सकता था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित हैं कि जिस समय दुनिया में संपत्ति सबसे तेजी से बढ़ रही है, उस समय गरीब देशों के बच्चों पर स्वास्थ्य खर्च का घट जाना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। आशंका जतायी जा रही है कि यदि स्वास्थ्य सहायता में तीस प्रतिशत की कटौती हो जाती है तो वर्ष 2045 तक 1.6 करोड़ अतिरिक्त बच्चों की मौत हो सकती है। विडंबना देखिए कि इस आसन्न संकट को नजरअंदाज करके विकसित देश अपने रक्षा व आंतरिक खर्च को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जबकि अमीर देशों द्वारा गरीब मुल्कों के बच्चों के स्वास्थ्य के लिये दिया जाने वाला पैसा उनके बजट के एक फीसदी से भी कम है। गेट्स फाउंडेशन का विश्व के अमीर देशों से आग्रह है कि वे दुर्लभ संसाधनों को उन स्थानों पर लक्षित करें, जहां वे सबसे अधिक जीवन बचा सकते हैं। दरअसल, संकट में वे बच्चे हैं, जो अपना पांचवां जन्मदिन मनाने से पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। इस संकट बढ़ने से दशकों से हासिल वैश्विक प्रगति बेकार हो जाएगी। निस्संदेह, दुनिया में कहीं भी पैदा हुए बच्चे को जीवित रहने और फलने-फूलने का अवसर मिलना चाहिए।

दरअसल, गेट्स फाउंडेशन की गोलकीपर्स रिपोर्ट और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने बताया कि 2024 में, 4.6 मिलियन बच्चों की पांचवें जन्मदिन से पहले मौत हो गई थी। आशंका है कि आर्थिक मदद में कटौती से इस वर्ष इस संख्या में दो लाख की वृद्धि से इसके बढ़कर 4.8 मिलियन बच्चों तक पहुंचने की आशंका है। जिसकी मूल वजह स्वास्थ्य के लिये वैश्विक मदद में आई बड़ी गिरावट है। इस वर्ष सहायता निधि में भारी कटौती के अलावा गरीब देशों के बढ़ते कर्ज, कमजोर स्वास्थ्य सिस्टम के चलते मलेरिया, एचआईवी और पोलियो जैसी बीमारियों के विरुद्ध हासिल उपलब्धियों को खोने का जोखिम बढ़ सकता है। हालिया रिपोर्ट बताती है कैसे प्रमाणित समाधानों और अगली पीढ़ी के नवाचारों में लक्षित निवेश से सीमित बजट में लाखों बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। निस्संदेह, गरीब मुल्कों के ये बच्चे सुरक्षित जीवन पाने के हकदार हैं। गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बिल गेट्स कहते हैं विश्व में गरीब मुल्कों के बच्चों के स्वास्थ्य रक्षा के लिये वित्तीय संसाधन बढ़ाने व वर्तमान सिस्टम में सुधार हेतु दक्षता बढ़ाने की जरूरत है। हमें कम संसाधनों में अधिक काम करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी पीढ़ी के दामन पर दाग लगेगा कि मानव इतिहास में सबसे उन्नत विज्ञान और नवाचार की पहुंच के बावजूद हम लाखों बच्चों का जीवन बचाने के लिये धन नहीं जुटा पाए। हम सही प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं तय करके तथा उच्च प्रभाव वाले समाधानों में निवेश करके बाल मृत्यु दर वृद्धि को रोक सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो हम वर्ष 2045 तक कई मिलियन बच्चों को जीवित रहने में मदद कर सकते हैं। इसके लिये जरूरी होगा कि हम विदेशी मदद का अधिकतम उपयोग करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, नियमित टीकाकरण, गुणवत्ता के टीके और डेटा के नये उपयोग पर अधिक ध्यान दें। निस्संदेह, इन बीमारियों से लड़ने के लिये वैश्विक प्रतिबद्धता को जारी रखने की जरूरत है। गेट्स फाउंडेशन का मानना है कि अगली पीढ़ी के नवाचारों के विकास में निवेश से हम बच्चों में होने वाले मलेरिया और निमोनिया जैसे कुछ घातक रोगों को हमेशा के लिये खत्म कर सकते हैं।

हिंदू आस्था का मान रखने वाले जज के खिलाफ पूरे विपक्ष का एकजुट होना चिंताजनक मिसाल है

> तिरुप्परनकुंद्रम का दीपथूण विवाद केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का मामला नहीं रह गया है; यह प्रशासनिक निष्पक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रही राजनीति की वास्तविकता का आईना बन चुका है।

हिंदू-बहुल भारत में आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हो गई है कि किसी हिंदू को अपने ही प्राचीन धर्मस्थल पर दीपक जलाने या पूजा करने के लिए अदालत से अनुमति लेनी पड़े? यह स्थिति आखिर क्यों पैदा हो गयी है कि न्यायालय पूजा की अनुमति दे दे तो सरकार उस अनुमति के क्रियान्वयन को ही रोक दे? यह स्थिति क्यों बन गयी है कि अदालत अनुमति दे दे तो कुछ राजनीतिक दल उस न्यायाधीश को ही पद से हटाने की मांग करने लगें जिसने हिंदुओं को अपने धर्म स्थल पर पूजा करने की अनुमति दी? क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक दृश्य है? सवाल उठता है कि तुष्टिकरण की राजनीति की आड़ में हिंदू आस्था को बार-बार क्यों चोट पहुँचायी जाती है? क्या बहुसंख्यक धर्म की परंपराएँ केवल इसलिए संदेह के घेरे में हैं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की राजनीति को धर्म और इतिहास से ऊपर रख चुके हैं? और क्या अब न्यायपालिका तक को इस आधार पर निशाना बनाया जाएगा कि उसका निर्णय किसी समुदाय को राजनीतिक रूप से असुविधाजनक लगा? इन मूलभूत प्रश्नों के बीच तिरुप्परनकुंद्रम का दीपथूण विवाद केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का मामला नहीं रह गया है; यह प्रशासनिक निष्पक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रही राजनीति की वास्तविकता का आईना बन चुका है। हम आपको बता दें कि मदुरै के तिरुप्परनकुंद्रम में अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और उससे सटे 'दीपथूण'

(पत्थर के दीप-स्तंभ) पर दीप प्रज्ज्वलन को लेकर उठा विवाद लगातार कानूनी और राजनीतिक टकराव का रूप लेता जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा 'दीपथूण' पर दीप जलाने की अनुमति देने के बाद राज्य सरकार ने न केवल इस आदेश को चुनौती दी बल्कि जिला प्रशासन ने भी पर्वत की तलहटी पर ही श्रद्धालुओं को रोक दिया। इस घटना ने न्यायपालिका और राज्य सरकार के बीच तनाव को सार्वजनिक रूप से उद्घाटित कर दिया। हम आपको बता दें कि 1 दिसंबर को न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने हिंदू तमिलर कच्ची के संस्थापक राम रविकुमार की याचिका पर आदेश देते हुए भक्तों को तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथूण पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। लेकिन 3 दिसंबर के कार्तिगई दीपम उत्सव के दिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया जिसके बाद रविकुमार ने अवमानना याचिका दायर की। उसी दिन न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने दस भक्तों को दीपथूण तक जाने और वहाँ दीप प्रज्ज्वलित करने की अनुमति दी तथा उनकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ कवर प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद पुलिस ने समूह को रोक दिया और राज्य सरकार ने अवमानना कार्यवाही से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हम आपको बता दें कि इस मामले की जड़ें लगभग सौ वर्ष पुरानी हैं। तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी, जो भगवान मुरुगन के छह प्रमुख पवित्र स्थलों (अरुपडई वीड़कु) में से एक है, वहां पर स्थित मंदिर और एक दरगाह के बीच 1920 से ही स्वामित्व और धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद रहा है। उस समय सिविल कोर्ट और बाद में प्रिवी काउंसिल ने पहाड़ी को मंदिर सम्पत्ति घोषित किया था। किंतु दीप प्रज्ज्वलन की परंपरा को लेकर न्यायालय ने 1996 में यह कहा था कि पारंपरिक स्थान मंदिर परिसर का उचिपिल्लैयार कोविल मंडपम है; हालांकि भविष्य में किसी वैकल्पिक स्थान पर दीप प्रज्ज्वलन की अनुमति HR&CE विभाग द्वारा दी जा सकती है, बशर्ते वह दरगाह से दूर हो।

इसके बाद भी दीपथूण को पारंपरिक स्थल बताकर कई याचिकाएँ दायर हुईं, जिन पर 2014 और 2017 में उच्च न्यायालय ने यह दोहराया था कि मंदिर प्रबंधन ही धार्मिक परंपराओं और स्थलों का निर्धारण करेगा। लेकिन इस वर्ष पुनः इस विवाद ने जोर पकड़ा और राजनीतिक रंग ले लिया। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दायर कर दी है। वहीं 5 दिसंबर को खंडपीठ ने मंदिर प्रबंधन का पक्ष रखते हुए यह चेतावनी दी कि न्यायपालिका का अपमान करने वाली टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर को अदालत ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और एडीजीपी (कानून-व्यवस्था) को 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का आदेश दिया, क्योंकि प्रशासन ने न्यायालय के पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया।

दूसरी ओर, यह विवाद इसी बीच संसद तक पहुँच गया है। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, एनसीपी (एसपी) और AIMIM से संबद्ध 107 विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वामीनाथन को हटाने का प्रस्ताव सौंपा। आरोप लगाया गया कि न्यायाधीश ने एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर निर्णय दिए और निष्पक्षता व धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा है। देखा जाये तो विपक्ष का यह कदम अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक टकराव बन चुका है, क्योंकि इसे न्यायपालिका पर सीधे प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने न्यायाधीश के निर्णय से असहमति को आधार बनाकर उन्हें हटाने का प्रस्ताव दिया, वह भारतीय लोकतंत्र में अभूतपूर्व और चिंताजनक मिसाल है।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी का इतिहास केवल मंदिर-प्रशासन से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह हिंदू आस्था का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है जहाँ सदियों से भक्तों की उपस्थिति रही है। 1920 के सिविल डिक्री और प्रिवी काउंसिल के निर्णय ने स्पष्ट कहा था कि पहाड़ी मंदिर की संपत्ति है तथा दरगाह उससे केवल कुछ सीमित हिस्सों में सम्बद्ध है। यह तथ्य अपने आप में बताता है कि दीपथूण पर दीप जलाना मंदिर-परिसर के भीतर ही धार्मिक अनुष्ठान का एक स्वाभाविक हिस्सा है।

फिर भी, पिछले तीन दशकों में दीपथूण को लेकर विवाद गहराता गया और प्रशासन ने अक्सर सुरक्षा या साम्प्रदायिक संवेदनशीलता का हवाला देकर हिंदू परंपराओं को सीमित किया। यह वही मानसिकता है जो डीएमके और उसके सहयोगियों की राजनीति में बार-बार दिखाई देती है, जहाँ बहुसंख्यक आस्था को दबाकर तुष्टिकरण को राजनीतिक लाभ का साधन बना दिया जाता है। यह संयोग नहीं है कि वही दल, जिसके नेताओं ने अनेक बार सनातन धर्म को नष्ट करने योग्य कहा, वही आज दीपथूण में दीप जलाने का विरोध कर रहा है।

यहाँ प्रश्न केवल परंपरा का नहीं, बल्कि अधिकारों का है। जब उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश मौजूद था कि भक्त दीपथूण पर दीप जला सकते हैं, तब राज्य सरकार द्वारा उसे लागू न करना न केवल न्यायालय की अवमानना है बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता का खुला हनन भी है। जिस प्रकार अदालत ने पुलिस और प्रशासन को फटकारते हुए कहा कि न्यायपालिका का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, वह बताता है कि सरकार किस हद तक अपनी सीमाएँ भूल चुकी है।

सरोकार

कला, प्रकृति और एक बालक की मासूम दृष्टि

एंटोन चेखव के बचपन की यह घटना सिर्फ एक स्मृति नहीं, बल्कि यह बताती है कि किसी भी मनुष्य के भीतर छिपी कला किस तरह प्रकृति की गोद में जन्म लेती है। जिस किंडरगार्टन में नन्हे चेखव को भेजा गया था, वहाँ का अनुशासन बड़ा कठोर माना जाता था। बच्चों को स्पष्ट आदेश दिया गया था कि वे फूलों को प्यार से देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में उन्हें तोड़ नहीं सकते। यह नियम बच्चों के लिए एक तरह का डर बन गया था—वे प्रकृति से प्रेम नहीं, बल्कि आदेशों के अनुसार व्यवहार कर रहे थे।

लेकिन चेखव का मन अलग था। वह बच्चा फूलों को देखकर सिर्फ मुस्कुराता नहीं था, बल्कि उन्हें अपने भीतर उतार लेता था। हरे पत्ते, रंग-बिरंगी पंखुड़ियाँ, हवा की हल्की सरसराहट—सब कुछ उसके भीतर गहरे उतर जाता था। और फिर वह चुपचाप अपनी कक्षा में जाता, कागज़ और रंग उठाता, और उन्हें ठीक उसी रूप में कागज़ पर उकेरने लगता। वह फूल उसके लिए एक वस्तु नहीं थे, बल्कि एक अनुभव थे, एक मित्र थे, एक रहस्य थे जिन्हें वह चित्रों में व्यक्त करना चाहता था।

किंडरगार्टन की संयोजिका ने जल्द ही यह भेद पकड़ लिया। जहाँ बाकी बच्चे किसी नियम की मजबूरी में फूलों की ओर देखते थे, वहीं चेखव बिना किसी डर के हर दिन फूलों, पत्तियों और प्रकृति को पूरे प्रेम से निहारता था। उसकी आँखों में एक अजीब-सी चमक थी—जैसे वह हर नए रंग को पहली बार खोज रहा हो। उसके बनाए चित्रों में एक ऐसी ताजगी थी जो किसी साधारण बालक के बस की नहीं। संयोजिका ने समझ लिया था कि यह लड़का सिर्फ सीख नहीं रहा, यह सृजन कर रहा है।

एक सप्ताह बाद चेखव की माँ को स्कूल बुलाया गया। माँ के मन में थोड़ी चिंता थी कि कहीं बच्चा किसी शरारत में तो नहीं पकड़ा गया। लेकिन संयोजिका ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह बालक किसी साधारण राह पर चलने के लिए नहीं बना। उन्होंने आग्रह किया कि चेखव को साहित्य और कला की ओर पूरी तरह बढ़ने दिया जाए। माँ ने कारण पूछा तो संयोजिका ने एक गहरी बात कही—₹किंडरगार्टन के सारे बच्चे डर के कारण प्रकृति से प्रेम करने का अभिनय कर रहे हैं। लेकिन केवल एक बच्चा ऐसा है जिसने फूलों को सच्चे दिल से अपनाया है। जो कला को अनुशासन नहीं, प्रेम समझता है। वही बच्चा आगे चलकर कला का सृजन करता है।₹

समय गुज़रा। वर्षों ने अपनी चाल चली। मासूम बालक बड़ा होता गया। और बीस साल बाद वही एंटोन चेखव अपने समय के सबसे संवेदनशील कहानीकारों में गिने जाने लगे। उनकी रचनाओं में वही कोमलता झलकती थी जो उन्होंने बाल्यावस्था में फूलों की पंखुड़ियों से सीखी थी। उनकी कहानियों में प्रकृति का सौंदर्य, मनुष्य के दिलों की नमी और जीवन की सूक्ष्म संवेदनाएँ मिली-जुली मिलती थीं—ठीक वैसे ही जैसे बचपन में वे फूलों के रंगों को कागज़ पर मिलाया करते थे।

चेखव की यह घटना हमें एक गहरा संदेश देती है। कला कभी किसी नियम, किसी डर, किसी जबरदस्ती से पैदा नहीं होती। कला केवल तब जन्म लेती है जब हृदय खुला हो, मन स्वतंत्र हो और दृष्टि में मासूमियत हो। जो व्यक्ति प्रकृति को सच्चे मन से अपनाता है, वही विश्व को नए रंगों में देख पाता है, और वही व्यक्ति कहानी, कविता, चित्र या संगीत के रूप में उस सौंदर्य को दुनिया को लौटा पाता है।

चेखव की कथा प्राकृतिक सौंदर्य और मानवीय संवेदनाओं के उस अनंत संगम की कहानी है जहाँ से सृजन का पहला बीज अंकुरित होता है। कला वहीं फलती है जहाँ प्रेम का स्पर्श हो, भय का नहीं।

ट्रंप के शांति समझौते को नकार फिर संघर्ष

ट्रंप ने जिस युद्ध विराम के हवाले से नोबेल पीस प्राइज़ पाने की दावेदारी ठोकी थी, वो एक झटके में एक्सपोज़ हो गई है। युद्ध विराम इतनी जल्दी टूट जायेगा, इसकी आशा व्हाइट हॉउस को भी नहीं थी। 8 दिसंबर को फिर से हुई झड़पों के लिए दोनों पक्ष एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। महीनाभर पहले 10 नवंबर को एक थाई सैनिक के लैंडमाइन से घायल होने के बाद से तनाव बढ़ गया था। कंबोडिया का आरोप है कि वह कई सौ किलोमीटर तक फैली एक साझा सीमा के कई विवादित हिस्सों पर थाई हमले का शिकार है। देश के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, थाई गोलाबारी में सात कंबोडियन नागरिक मारे गए हैं और 20 अन्य घायल हुए हैं। दूसरी ओर बैंकॉक ने नोम पेन्ह पर आरोप लगाया है, कि व्हाइट हाउस द्वारा खून-खराबा रोकने की चेतावनी के बावजूद उसने बॉर्डर पार रॉकेट हमले किए।

कंबोडिया की सीमा कुल तीन देशों से मिलती है। पश्चिम और उत्तर में थाईलैंड है, तो उत्तर में लाओस स्थित है। पूर्व और दक्षिण पूर्व में वियतनाम है तो दक्षिण में कंबोडिया की सीमा थाईलैंड की खाड़ी से मिलती है। 9 नवंबर, 1953 को फ्रांस ने कंबोडिया को आजाद कर दिया। वर्ष 1863 से 1953 के कालखंड में कंबोडिया पर फ्रांस के कब्ज़े के दौरान ही थाईलैंड (जिसे उस समय सियाम कहा जाता था) के साथ कंबोडिया की सीमाएं तय की गई थीं, विशेषकर 1907 के सीमा निर्धारण में, जिससे कई विवादित क्षेत्र बने, उनमें से एक है प्रीह विहियर मंदिर, जो आज भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है।

प्रीह विहियर मंदिर पर थाई-कंबोडियाई क्षेत्रीय विवाद 2008 में भड़क गया, जब थाई सरकार ने एक संयुक्त विज्ञप्ति पर सह-हस्ताक्षर किया, जिसने मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए यूनेस्को को कंबोडिया के अनुरोध का समर्थन किया। इस कदम से थाईलैंड में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और यहां तक कि 2008 से 2011 की अवधि में दोनों देशों के बीच सशस्त्र झड़पें भी हुईं।

इस साल अक्तूबर तक थाई-कम्बोडिया के बीच फुल स्केल वॉर में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और लगभग 40 हज़ार से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा। विवाद से निपटारे के लिए द्विपक्षीय वार्ता विफल रही। आसियान द्वारा मध्यस्थता और शांति स्थापना प्रयासों के साथ भी यही हुआ। फिर आसियान सम्मेलन के दौरान 25 अक्तूबर, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने घोषणा की थी कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 'ऐतिहासिक' शांति समझौते पर हस्ताक्षर करवा दिये हैं। ट्रम्प ने उसे आधार बनाकर नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी ठोक दी। अब इसका मज़ाक़ बनना शुरू हो चुका है।

अब सवाल यह है, क्या ट्रंप केवल शांति समझौता का क्रेडिट लेने की जल्दी में थे? क्या उन्हें समस्या की तह तक नहीं जाना चाहिए था? ट्रंप इसी तरह शांति स्थापना की सतही घोषणा भारत-पाकिस्तान के सन्दर्भ में करते रहे हैं। यूक्रेन-रूस के बीच शांति प्रयासों का मज़ाक़ अलग बन रहा है। ट्रंप की तथाकथित शांति स्थापना से ग़ज़ा में शांति नहीं दिख रही। विश्लेषकों का कहना है कि युद्धविराम के बाद से गाजा में इस्राइल द्वारा फलस्तीनियों की हत्या की दर धीमी हो गई है, लेकिन युद्ध जारी है। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी मध्यस्थता वाली योजना का दूसरा चरण करीब है। लेकिन मुख्य मुद्दों को अभी भी हल करने की ज़रूरत है। मतलब साफ़ है, ट्रम्प ने जहां-जहां शांति स्थापना का ढोल पीटा, वहां अशांति दोबारा भड़की है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच दोबारा से युद्ध छिड़ जाना ट्रम्प की विफलता का दूसरा उदाहरण है।

मलेशिया, जो अभी आसियान का चेयरमैन है, ने बीच-बचाव करने की पेशकश की थी। मगर, इस हड़बड़ी के विवाद में मलेशिया भी कम दोषी नहीं है। वह इसे डिप्लोमैटिक जीत मान रहा था, लेकिन उसने अंदर की अनसुलझी शिकायतों को नज़रअंदाज़ कर दिया। पिछली 25 अक्तूबर, 2025 को आत्ममुग्ध ट्रम्प ने सीज़फ़ायर की घोषणा के बाद, इसका पूरा क्रेडिट लिया। सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने कहा था, 'मैंने थाईलैंड के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात की। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दोनों टैरिफ धमकी के बाद शांति समझौते के लिए राजी हो गए हैं। सभी को बधाई। मैंने अपनी ट्रेड टीम को बातचीत फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है।' अफ़सोस, सिर्फ 42 दिन बाद ट्रम्प के तथाकथित शांति समझौते की धज्जियां उड़ गईं। ठीक से देखा जाये, तो उन दिनों चीन की भागीदारी ज़्यादा बारीक थी। चीन ने धमकाने की बजाय डिप्लोमैटिक ऑब्ज़र्वर तैनात करते हुए क्षेत्रीय संयम और आसियान प्रक्रिया का सम्मान करने की आम अपील की। 27 जुलाई, 2025 को विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया था, 'चीन दोनों तरफ हुए नुकसान से बहुत दुखी है और दिल से हमदर्दी दिखाता है।

नजरिया

जब कोलकाता की काली माँ ने चाइना टाउन की खुशबू को प्रसाद बना लिया

उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

भारत में मंदिरों की विविधता उतनी ही विशाल है जितनी इसकी संस्कृति। कहीं प्रसाद में लड्डू मिलता है, कहीं खीर, कहीं चावल, कहीं गुड़; लेकिन देश की भीड़भाड़ और इतिहास से भरी नगरी कोलकाता के बीचोंबीच एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जहाँ देवियों की पूजा के साथ प्रसाद में मिलता है—मोमोज, चाऊमीन और फ्राइड राइस।

पहली बार सुनने पर यह बात हर किसी को चौंका देती है, लेकिन तांग्रा क्षेत्र—जिसे लोग प्यार से चाइना टाउन कहते हैं—वहाँ स्थित मां काली का यह मंदिर भारतीय और चीनी संस्कृति के मिलन की सबसे खूबसूरत मिसाल है।

इस मंदिर में आने वाला कोई भी भक्त यह सोचकर नहीं आता कि उसे फल, मेवे या मिठाई मिलेगी। यहाँ प्रसाद की थाली से उठती भाप में मोमोज का स्वाद होता है और चाऊमीन की सुगंध में माँ काली की कृपा का आशीर्वाद घुला रहता है।

इस मंदिर की कहानी उतनी ही चमत्कारी है जितनी अनोखी। कहा जाता है कि बहुत समय पहले इसी इलाके में एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने हार मान ली, लेकिन उसके माता-पिता ने नहीं। उस समय यहाँ एक पेड़ के नीचे दो काले पत्थर रखकर माँ काली की पूजा की जाती थी। बच्चे को इसी पेड़ के नीचे लिटाया गया और माता-पिता ने काली माँ से प्रार्थना की—"हे माँ, यदि हमारा बच्चा ठीक हो गया तो हम यहाँ एक भव्य मंदिर बनाएंगे।"

मान्यता है कि तभी माँ काली ने अपना चमत्कार दिखाया। जिस बच्चे को डॉक्टरों ने बचने की उम्मीद नहीं बताई थी, वह अचानक उठ बैठा। लोग कहते हैं कि उस पल से पेड़ के नीचे रखे पत्थरों में शक्ति समा गई। समय के साथ वहाँ मंदिर बना और यह स्थान श्रद्धा का केंद्र बन गया।

मंदिर की एक दूसरी कहानी तांग्रा क्षेत्र के इतिहास से भी जुड़ती है। सिविल वॉर के समय कई चीनी परिवार इस इलाके में आकर रहने लगे। वे अपनी संस्कृति, खाना और जीवनशैली साथ लेकर आए थे। जब उन्होंने माँ काली की शक्ति के बारे में सुना, तो उन्होंने देवी को वही भोग चढ़ाया जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय था—मोमोज, चाऊमीन और फ्राइड राइस।

उनकी यह भेंट स्वीकार हुई, और उस दिन से यह प्रसाद मंदिर की परंपरा बन गया।

आज यह मंदिर न केवल हिंदू भक्तों का, बल्कि चीनी समुदाय का भी केंद्र है। पूजा में अगरबत्ती की खुशबू के साथ चाइनीज व्यंजनों की महक मिल जाती है। बाहर बोर्ड पर "मां काली" चीनी भाषा में भी लिखा है—जैसे दो संस्कृतियाँ एक ही आस्था से जुड़कर एक हो गई हों। जब कोई इस मंदिर में प्रसाद ग्रहण करता है, तो वह केवल खाना नहीं खाता, बल्कि भारत और चीन की मिलती संस्कृतियों का स्वाद चखता है।

ये मंदिर यह साबित करता है कि आस्था की दुनिया में न तो भाषा की दीवारें होती हैं, न भोजन की। माँ का प्रसाद वही है जो उनका भक्त प्रेम से चढ़ाए—फिर चाहे वह चावल के लड्डू हों या गरमा-गरम मोमोज।

यदि कभी कोलकाता जाएँ, तो तांग्रा के इस मंदिर तक ज़रूर पहुँचिए।

वहाँ की हवा में घुली एक अनोखी शक्ति, उसकी कहानी का चमत्कार और मोमोज का स्वाद—तीनों मिलकर आपको एहसास दिलाते हैं कि श्रद्धा के मार्ग पर कभी कोई चीज़ असंभव नहीं होती।

मालिक जयेश जग्शी गाला हेतु प्रकाशक, मुद्रक **अश्विनी कुमार दुबे** द्वारा मोदी प्रिंटर्स, 24 बोमनजी लेन, फोर्ट, मुंबई-400001 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर्स, 28, डॉ. भगवानदास इंद्रजीत रोड, वालकेश्वर, मलबार हिल, मुंबई-400006 से प्रकाशित किया।
संपादकः **अश्विनी कुमार दुबे** (पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी है, न्याय क्षेत्र मुंबई) कार्यकारी संपादकः अरविंद मिश्रा, सहसंपादकः सुजीत मिश्रा (दै.'राष्ट्रीय स्वाभिमान 'में सभी लोग सहयोगात्मक और अवैतनिक तौर पर कार्यरत हैं)
● आर.एन.आई.:MAHHIN/2008/24084 ● ईमेलः rastriyaswabhiman@gmail.com ● भ्रमणध्वनि क्र. +919224733113

मालवणी स्कूल शिक्षक भर्ती पर उठे सवाल—अयोग्य नियुक्तियों के आरोपों ने शिक्षा तंत्र को झकझोरा, सरकार ने जांच के आदेश दिए

मुंबई की तेज़ रफ्तार जिंदगी के बीच एक शांत-सा इलाका है मालाड पश्चिम का मालवणी टाउनशिप। यहाँ की गलियों में इन दिनों एक अजीब-सी हलचल है। माता-पिता स्कूल के बाहर जमा हैं, बच्चे कान लगाकर बड़े-बड़ों की बातचीत सुन रहे हैं, और शिक्षक खुद असमंजस में हैं कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। यह सब उस आरोप के बाद शुरू हुआ जिसने न केवल बीएमसी के शिक्षा विभाग को कठघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि पूरे शहर में सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिए। आरोप यह कि 'मुंबई पब्लिक मालवणी टाउनशिप स्कूल' में एक निजी संस्था की ओर से ऐसे शिक्षकों को नौकरी पर रखा गया जो योग्य नहीं थे, और योग्य टीईटी पास शिक्षकों को जानबूझकर यहाँ-वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया।

मामला तब और बड़ा हो गया जब नागपुर विधानसभा सत्र में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस विधायक असलम शेख ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह किसी एक स्कूल का मामला नहीं है, बल्कि यह उन हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल है जो उसी भरोसे स्कूल आते हैं कि उनके शिक्षक प्रशिक्षित और योग्य होंगे। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट और आरटीई कानून के नियमों को किनारे रखकर मनमाने ढंग से अयोग्य लोगों को कक्षा में बैठा दिया गया—वह भी ऐसे समय में जब 2013 से टीईटी या सीटीईटी पास करना शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य है।

असलम शेख ने विधानसभा में वह तस्वीर भी खींची जो मालवणी क्षेत्र के अभिभावक पिछले कई महीनों से महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग्य टीईटी पास शिक्षकों का अचानक ट्रांसफर कर देना और उनकी जगह ऐसे लोगों को बैठा देना जिनके पास न अनुभव है, न आवश्यक प्रमाण, बच्चों के अधिकारों के साथ सीधा खिलवाड़ है। उनका कहना था कि जिस निजी संस्था को प्राइमरी से सेकेंडरी तक की कक्षाएँ सौंप दी गईं, उसने बुनियादी सरकारी नियमों की अनदेखी करते हुए अपनी मर्जी से भर्तियाँ कीं।

इन सवालों ने स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे को तुरंत हरकत में ला दिया। उन्होंने विधानसभा में घोषणा की कि इस पूरे मामले की जांच होगी और किसी भी स्तर पर नियमों की अवहेलना सामने आई तो कार्रवाई भी जरूर होगी। यह घोषणा मालवणी के अभिभावकों के लिए राहत जरूर थी, लेकिन उनकी चिंताओं का अंत नहीं। उन्हें डर है कि जांच में समय लगेगा, पर उनके बच्चों की पढ़ाई तो हर दिन प्रभावित हो रही है।

उधर, सरकार की ओर से राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने विधानसभा में अपना पक्ष रखते हुए कृत किया कि भर्ती बीएमसी की नीति के अनुसार ही हुई है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के साथ हुई गलतफहमियों को दूर किया गया है और यह कहना गलत है कि अयोग्य शिक्षकों को नियमविरुद्ध तरीके से नियुक्त किया गया। लेकिन इस जवाब से असलम शेख शांत नहीं हुए। उन्होंने दोहराया कि टीईटी अनिवार्य है और जब तक इस बिंदु पर स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, तब तक मामले को बंद नहीं किया जा सकता।

इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित वे बच्चे हैं जिनकी कक्षा के शिक्षक हर कुछ हफ्तों में बदल जाते हैं। एक सातवीं कक्षा की छात्रा ने अपने पिता से पूछा—"पापा, हमारी मैडम क्यों चली गईं? नई मैडम को कुछ समझ में नहीं आता।" यही सवाल कई अभिभावक भी घर में, स्कूल में, और अब विधानसभा तक पूछ रहे हैं। उन्हें डर है कि सरकारी स्कूलों में लगातार घटती गुणवत्ता कहीं उनके बच्चों के भविष्य पर भारी न पड़ जाए।

मालवणी में इस हंगामे के बीच शिक्षा की एक गहरी चिंता भी सामने आई है—क्या सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं को सौंपते समय पर्याप्त निगरानी होती है? क्या नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाती है?

मुंबई दो दिनों तक प्यासेपन की कगार पर: बीएमसी के बड़े पाइपलाइन शटडाउन से शहर के कई इलाके 24 घंटे पानी से महरूम

मुंबई जैसे महानगर के लिए पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि हर दिन की धड़कन है। और जब इस सप्लाई पर शटडाउन का ऐलान होता है, तो जिंदगी की रफ्तार भी ठहर जाती है। आने वाले 12 और 13 दिसंबर को ऐसा ही एक बड़ा विराम मुंबई के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहन्मुंबई नगरपालिका निगम यानी बीएमसी ने अपने प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क के अपग्रेड और कनेक्शन कार्य के कारण पूरे 24 घंटे पानी सप्लाई बंद रखने का फैसला किया है। यह बंद शुक्रवार सुबह 9 बजे से शुरू होकर शनिवार सुबह 9 बजे तक जारी रहेगा। शहर के के-ईस्ट, एच-ईस्ट और जी/नॉर्थ वार्ड के कई बड़े इलाके इस शटडाउन से प्रभावित होंगे। बीएमसी के अनुसार यह काम सिर्फ एक सामान्य मेंटेनेंस नहीं, बल्कि शहर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए पानी वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम है।

बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि जिन पाइपलाइनों पर काम होना है, वे शहर की सबसे महत्वपूर्ण और भारी भरकम लाइनों में शामिल हैं। 1800 मिमी तानसा वेस्ट वॉटर मेन, 1200 मिमी वॉटर मेन, 2400 मिमी वैतरणा वॉटर मेन और जी/नॉर्थ वार्ड में 1500 मिमी वॉटर मेन—ये वे बड़े पाइप हैं जिनके सहारे मुंबई का पानी घर-घर पहुंचता है। इन पर नए कनेक्शन जोड़ना, पुराने हिस्सों को बदलना और नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना ऐसा काम है जिसे बिना शटडाउन के करना असंभव है। नगर निगम का कहना है कि भविष्य में पानी के दवाब को स्थिर रखने, लीक कम करने और बड़े हिस्सों में बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है।

शहर की आबादी को इस असुविधा के लिए तैयार रहने की सलाह देते हुए बीएमसी ने चेतावनी दी है कि कुछ जगहों पर शटडाउन के साथ-साथ पानी का दबाव भी काफी कम हो सकता है। विशेष रूप से के-ईस्ट वार्ड में यह दिक्कत अधिक महसूस होगी। कई रहवासी इलाकों में सुबह और शाम के समय, जब सामान्यतः पानी का दबाव बढ़ा रहता है, वहां इस बार नल सूने रहेंगे और लोगों को वैकल्पिक इंतजाम पहले से करने होंगे।

जी/नॉर्थ वार्ड के इलाके इस शटडाउन का भारी असर झेलेंगे। 12 दिसंबर को धारावी लूप रोड, A.K.G नगर, धारावी मेन रोड, गणेश मंदिर रोड, दिलीप कदम रोड, जैस्मीन मिल रोड और माहिम फाटक जैसे स्थानों पर पानी पूरी तरह बंद रहेगा।

शिंदे गुट शिवसेना में बड़ी जिम्मेदारी: साबू चेरियन बने कल्याण पूर्व उप-शहर प्रमुख कल्याण

शिंदे गुट शिवसेना में संगठन विस्तार और मजबूत संरचना के तहत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेतृत्व ने साबू चेरियन को कल्याण पूर्व उप-शहर प्रमुख के पद पर नियुक्त किया है।यह नियुक्ति जिला प्रमुख गोपाल जी लांडगे, महिला जिला प्रमुख छाया ताई वाघमारे, उप जिला प्रमुख रमाकांत देवलेकर और हर्षवर्धन पलांडे द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की गई।पार्टी की स्थानीय इकाई ने इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति और मजबूती मिलेगी।इस मौके पर कल्याण शहर प्रमुख निलेश शिंदे, हर्षल साल्वी, नवीन सिंह, अवधेश सिंह, प्रभाकर गुप्ता और विनोद मिश्रा सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।पार्टी पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि साबू चेरियन अपनी ऊर्जा और अनुभव से कल्याण पूर्व में शिवसेना (शिंदे गुट) को और अधिक सशक्त और सक्रिय बनाएंगे।

चलती ट्रेन में करोड़ों का सोना गायब: सिद्धेश्वर एक्सप्रेस में व्यापारी के गहनों की रहस्यमयी चोरी से रेलवे सुरक्षा पर बड़ा सवाल

मुंबई की ओर दौड़ती सिद्धेश्वर एक्सप्रेस की रात उस व्यापारी के लिए कभी न भूलने वाली बन गई, जो अपने बैग में लाखों नहीं, बल्कि पूरे 5.5 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण लेकर जा रहा था। यह घटना न सिर्फ उसके लिए सदमे की तरह सामने आई, बल्कि मुंबई तक फैली रेलवे सुरक्षा व्यवस्थाओं की परतें भी एक बार फिर उघड़ गईं। व्यापारी अभय जैन, जो गोरेगांव के रहने वाले और पिछले कई वर्षों से सोना–चांदी के बड़े व्यवसायी हैं, अपनी बेटी के साथ यात्रा पर थे। उन्हें शायद ही यह अंदेशा रहा होगा कि एसी कोच जैसा सुरक्षित माना जाने वाला क्षेत्र भी इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने वालों के लिए एक आसान निशाना बन सकता है।

अभय जैन ने अपनी बेटी को साथ लेकर उस रात सोलापुर से मुंबई की ओर सफर शुरू किया था। उनके बैग में लगभग साढ़े चार किलो सोने के गहने थे, जिन्हें वह किसी व्यापारिक कार्य के लिए लेकर जा रहे थे। कर्जत और कल्याण स्टेशन के बीच ट्रेन अपनी नियमित गति से आगे बढ़ रही थी कि इसी दौरान किसी क्षण में वह बैग गायब हो गया। व्यापारी ने जब बैग को सीट के नीचे देखा तो उनका दिल एक पल को थम गया। जिस बैग में करोड़ों का सामान रखा था, वह वहां नहीं था। एसी डिब्बे में ऐसी हरकत कैसे हुई, किसने की, किस समय की—इन सारे सवालों का जवाब उस समय किसी के पास नहीं था।

घटना का अहसास होते ही जैन ने तत्काल कल्याण लोहमार्ग पुलिस को फोन किया और फिर स्टेशन पहुंचते ही औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही मामला सिर्फ स्थानीय थाना सीमा का नहीं रहा बल्कि रेलवे क्राइम ब्रांच भी इसमें सक्रिय हो गई। दोनों एजेंसियों ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की, क्योंकि चोरी की रकम इतनी बड़ी थी कि इसे किसी साधारण चोर की करतूत मानना मुश्किल था। पुलिस को शुरुआती जांच में यह स्पष्ट होता गया कि चोरी कोई अवसर देखकर की गई घटना नहीं, बल्कि पूरी तरह योजनाबद्ध कार्रवाई थी। चोरों को शायद यात्रा की जानकारी थी, शायद बैग की प्रकृति का अंदाजा था, और यह भी संभव है कि वे ट्रेन में ही किसी अवसर की तलाश में सवार हुए हों।

कर्जत से कल्याण के बीच रेलवे लाइनों पर कई जगह लगाए गए सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस टीम खंगाल रही है। फुटेज की यह छानबीन बेहद समय लेने वाली है, पर जांचकर्ताओं को उम्मीद है कि किसी न किसी बिंदु पर चोरों के कदमों की छाप अवश्य मिल जाएगी। रेलवे पुलिस ने चोरी का पता चलने के बाद तुरंत चार विशेष टीमें बनाईं जो अलग-अलग दिशा में लगाई गईं—कुछ रेलवे स्टेशनों पर, कुछ संभावित ठिकानों पर और कुछ उस रूट के आसपास जहां चोर उतर सकते थे।

जांच अधिकारी पंढरी कांडे ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ सुराग सामने आ रहे हैं और अगले कुछ दिनों में मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है। क्राइम ब्रांच भी कुछ संदिग्ध यात्रियों की सूची तैयार कर रही है और टिकट बुकिंग रिकॉर्ड की भी जांच चल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं यह चोरी किसी संगठित गिरोह का हिस्सा तो नहीं।

यह घटना एक बार फिर यह सवाल उठाती है कि क्या एसी कोच जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह भी असल में सुरक्षित हैं? क्या रेलवे सुरक्षा तंत्र बड़े शहरों के यात्रियों पर भरोसा करने योग्य है?

उबाठा गुट के ढोंगी हिन्दुत्व का पर्दाफाश: परंपरा पर प्रहार से छिड़ा नया राजनीतिक तूफ़ान

मुंबई की सियासी फिज़ा में इन दिनों एक ऐसा तूफ़ान उठ खड़ा हुआ है, जिसने हिंदुत्व की राजनीति करने वाले दलों की कथनी और करनी के बीच के गहरे अंतर को उजागर कर दिया है। 1 दिसंबर को न्यायमूर्ति स्वामीनाथन द्वारा मदुरै स्थित मंदिर में 'तिरुपरनकुंद्रम दीपम' प्रज्वलन की सदियों पुरानी परंपरा को पुनः शुरू करने का निर्देश दिया गया। यह आदेश धार्मिक अधिकार और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को संरक्षण देने वाली भारतीय न्याय-परंपरा की निरंतरता का प्रतीक माना गया। परंतु इस फैसले के विरोध में उबाठा गुट के एक सांसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर कर डाले जाने से न केवल राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई, बल्कि यह भी स्पष्ट हो गया कि परंपरा के प्रति सम्मान और हिंदुत्व की रक्षा के जो बड़े-बड़े दावे कुछ नेता वर्षों से करते आए हैं, वह सिर्फ मंचों तक सीमित रहते हैं और जब वास्तविक मुद्दा सामने आता है, तो वही लोग परंपरा को चोट पहुंचाने वालों की कतार में खड़े मिलते हैं। भाजपा के मीडिया प्रमुख नवनाथ बन ने इस कदम को हिंदुत्व-विरोधी मानसिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दीप प्रज्वलन की परंपरा पर रोक लगाने या उसे बहाल करने के न्यायिक आदेश का विरोध करना केवल धार्मिक अस्मिता पर हमला नहीं बल्कि हिंदू समाज को भ्रमित करने वाली वह राजनीति है, जो मंच पर धर्म की बात करती है और व्यवहार में धार्मिक मूल्यों की उपेक्षा करती है। नवनाथ बन ने खुला सवाल रखा कि क्या उबाठा गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने ही सांसद की इस विवादित और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली कार्रवाई से सहमत हैं। यदि वे सहमत नहीं हैं, तो क्या वे इस पर कार्रवाई करेंगे, या फिर राजनीतिक मजबूरियों के चलते इसे अनदेखा कर देंगे?

विजय दिवस पर सनी देओल की 'बॉर्डर 2' का टीज़र लॉन्च, फिल्म के सितारों ने बढ़ाई दर्शकों की उत्सुकता

सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' के टीज़र को लेकर मुंबई और पूरे बॉलीवुड में अब से लेकर 16 दिसंबर तक चर्चा का माहौल लगातार गर्म रहेगा। 'गदर 2' और 'जाट' जैसी फिल्मों की शानदार सफलता के बाद सनी देओल ने दर्शकों की उम्मीदों को फिर से एक नई ऊँचाई दी है और अब 'बॉर्डर 2' में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे बड़े सितारे भी शामिल हैं, जिससे फिल्म का पैमाना और दर्शकों की उत्सुकता दोनों बढ़ गई हैं। फिल्म के निर्माताओं ने हाल ही में सभी मुख्य कलाकारों की पहली झलक जारी की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर प्रशंसकों का जोश और बढ़ गया है और टीज़र रिलीज के इवेंट को लेकर उत्सुकता चरम पर पहुँच गई है। 'बॉर्डर 2' का टीज़र विजय दिवस, 16 दिसंबर 2025 को मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। पहले इस टीज़र को अमृतसर में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसे अंतिम समय में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। कार्यक्रम में निर्देशक अनुराग सिंह, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की उपस्थिति लगभग तय मानी जा रही है, जबकि सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा भी इस इवेंट में शामिल होने की संभावना है। इस भव्य समारोह में सितारों की मौजूदगी फिल्म के टीज़र के प्रभाव और उत्साह को कई गुना बढ़ाने वाली है। फैंस की सबसे बड़ी उत्सुकता इस बात को लेकर है कि क्या इस कार्यक्रम में सनी देओल भी उपस्थित रहेंगे। हाल ही में 24 नवंबर को उनके पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद से सनी किसी भी सार्वजनिक समारोह में दिखाई नहीं दिए हैं। उनकी अनुपस्थिति के बावजूद, टीज़र लॉन्च की खबर ने प्रशंसकों को रोमांचित कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि यह महत्वपूर्ण इवेंट उनके करियर और फिल्म की सफलता के लिए विशेष महत्व रखता है, इसलिए टीम को विश्वास है कि सनी देओल इस समारोह में उपस्थित होंगे और अपने प्रशंसकों से जुड़ेंगे। टीज़र रिलीज के साथ ही फिल्म का प्रचार और देशभर में सिनेमा प्रेमियों के बीच चर्चा का माहौल चरम पर पहुँच जाएगा। 'बॉर्डर 2' का टीज़र केवल एक छोटी झलक नहीं, बल्कि फिल्म की कहानी, पैमाना और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फैंस को उम्मीद है कि टीज़र से पता चलेगा कि सनी देओल और बाकी कलाकार फिल्म में कितनी ऊर्जा और जज़्बा लेकर आए हैं। इस मौके पर फिल्म के निर्देशक और कलाकार अपने अनुभव और फिल्म के पीछे की मेहनत के बारे में भी साझा करेंगे, जिससे दर्शकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि फिल्म को बनाने में कितनी तैयारी और प्रयास किए गए हैं। जैसे ही 16 दिसंबर को टीज़र सामने आएगा, फिल्म के बारे में लोगों में चर्चा और उत्सुकता बढ़ जाएगी और सिनेमाघरों में इसकी रिलीज़ के लिए दर्शकों की प्रतीक्षा और भी जोरों पर होगी। 'बॉर्डर 2' का टीज़र न केवल फिल्म की शुरुआती झलक देगा, बल्कि यह दर्शकों को यह एहसास भी कराएगा कि सनी देओल और उनकी टीम ने इस फिल्म को बनाने में हर संभव प्रयास किया है और विजय दिवस पर यह टीज़र रिलीज़ होना इसके प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। इस भव्य इवेंट और टीज़र के आने के बाद फिल्म का माहौल पूरी तरह गर्म हो जाएगा और दर्शकों की उम्मीदें फिल्म की रिलीज तक लगातार बनी रहेंगी।

न्यू ईयर पार्टी में धमाका: 'राहु केतु' का पहला गाना 'मदिरा' रिलीज होते ही मचा रहा धमाल

न्यू ईयर के जश्न और पार्टी सीजन को और रंगीन बनाने के लिए बॉलीवुड में एक और जोश भरी पेशकश आ गई है। ज़ी स्टूडियोज़ और बीलाइव प्रोडक्शन्स की फिल्म 'राहु केतु' का पहला गाना 'मदिरा' रिलीज होते ही सोशल मीडिया और संगीत प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने लगा है। लंबे इंतज़ार और टीज़र रिलीज के बाद सामने आया यह गाना दर्शकों को अपनी मस्ती, एनर्जी और हटके स्टाइल से पूरी तरह आकर्षित कर रहा है। टीज़र में फिल्म की मजेदार, कॉस्मिक और पूरी तरह अलग दुनिया का अनुभव हुआ था, वहीं गाने 'मदिरा' ने इस अनुभव को और जीवंत कर दिया है, जो इस साल के हर न्यू ईयर और पार्टी सीज़न का अनोखा एंथम बनते हुए नजर आ रहा है। गाने में शालिनी पांडे की बोल्ड और ग्लैमरस पर्सनैलिटी ने सभी की निगाहें अपनी ओर खींची हैं। उनका एनर्जेटिक और स्मूद डांस मूव्स, गाने की वाइब को हाई-ऑक्टेन बनाते हैं, वहीं पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा ने अपनी मजेदार केमिस्ट्री और बिंदास अंदाज़ से पार्टी नंबर को और भी धमाकेदार बना दिया है। शार्प कोरियोग्राफी और कलाकारों की एंट्री, एक्सप्रेशन्स और स्टाइल ने इसे देखने और सुनने लायक परफेक्ट एंटरटेनमेंट ट्रैक बना दिया है। गाने 'मदिरा' के संगीतकार विक्रम मॉन्ट्रोज़ ने इसे कंपोज़ किया है और अपनी आवाज़ के साथ सिमर कौर और अभिनव शेखर ने इसे और भी जीवंत बना दिया है। गाने के बोल भी अभिनव शेखर ने लिखे हैं और इसे सुनते ही साफ हो जाता है कि यह ट्रैक सिर्फ मस्ती भरने के लिए नहीं, बल्कि फिल्म 'राहु केतु' की पूरी एनर्जी, पागलपन और बिंदास स्टाइल को सही तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। विक्रम मॉन्ट्रोज़ ने कहा कि यह गाना बस मूड में आने और पल को जीने के लिए बनाया गया है। फिल्म 'राहु केतु' के निर्देशन का जिम्मा विपुल गर्ग ने संभाला है, और इसे ज़ी स्टूडियोज़ ने पेश किया है। निर्माण भी ज़ी स्टूडियोज़ और बीलाइव प्रोडक्शन्स ने मिलकर किया है। फिल्म की रिलीज़ डेट 16 जनवरी 2026 तय की गई है और इसके पहले गाने और टीज़र ने ही दर्शकों के बीच फिल्म के प्रति उत्सुकता और भी बढ़ा दी है।

प्रियंका चोपड़ा का पुराना संघर्ष यादों में लौटा: महत्वाकांक्षा, त्याग और तपस्या से बनी एक वैश्विक पहचान

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जब किसी बड़े मंच पर अपने जीवन का दरवाज़ा थोड़ा-सा खोलकर भीतर की सच्चाई दिखाती हैं, तो दुनिया को यह समझने में देर नहीं लगती कि चमचमाती सफलता के पीछे कितनी रातें जागकर बिताई गईं, कितनी खुशियाँ टाली गईं और कितने त्याग किए गए। अबू धाबी में आयोजित ब्रिज समिट के दौरान प्रियंका ने अपने शुरुआती दिनों का वह दौर याद किया, जब वह इंडस्ट्री में नई थीं, बेहद महत्वाकांक्षी थीं और अवसरों की तलाश में हर उस काम के लिए 'हाँ' कह देती थीं, जो उनके रास्ते में आता था। उन्होंने कहा कि अपने शुरुआती 20 के दशक में वह इतनी भूखी थीं सफलता के लिए कि सप्ताह, महीना, त्योहार—किसी का इंतजार किए बिना बस काम करती चली जाती थीं। उनके लिए काम मिलना ही उपलब्धि थी और उस उपलब्धि को दोनों हाथों से पकड़ने के लिए वह हर कीमत चुकाने को तैयार थीं। प्रियंका ने बताया कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया—जन्मदिन मनाने की खुशी, दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहारों की रोशनी, घर पर परिवार के साथ बिताए जाने वाले वे छोटे-छोटे पल जिनकी कीमत वह आज के समय में समझती हैं। उन्होंने बताया कि यहां तक कि जब उनके पिता अस्पताल में भर्ती थे, तब भी वह उनके पास देर तक नहीं रुक सकीं क्योंकि काम से छुट्टी लेना संभव नहीं था। उस दौर की तपस्या, अनगिनत त्याग और लगातार चलने वाली थकानभरी जद्दोजहद ने उन्हें तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह और मजबूत होती गईं। उन्होंने कहा कि आज जब वे अपनी उस यात्रा को पीछे मुड़कर देखती हैं, तो उन्हें समझ आता है कि अगर उन्होंने तब वह भारी मेहनत न की होती, तो आज वे यह स्वतंत्रता नहीं जी पातीं—वह स्वतंत्रता जिसमें वह फिल्में चुन सकती हैं, कहानियों का चयन कर सकती हैं और अपने समय को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार नियोजित कर सकती हैं। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज वह खुद को धन्यवाद देती हैं, उस युवा लड़की को जो हर दिन काम पर निकलती थी और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर त्याग स्वीकार कर लेती थी।

रेमो डिसूजा की नई फिल्म 'टेढ़ी है पर मेरी है' का टीज़र जारी, महवश को मिला बड़ा ब्रेक

बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूजा ने अपनी नई फिल्म 'टेढ़ी है पर मेरी है' की आधिकारिक घोषणा कर दी है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इसका टीज़र वीडियो भी साझा किया, जिसमें फिल्म की स्टारकास्ट और कहानी की झलक सामने आई। यह फिल्म खासतौर पर इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इसके जरिए रेमो ने आरजे महवश को बड़ा ब्रेक दिया है, जो हाल ही में भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की कथित गर्लफ्रेंड के तौर पर चर्चा में रही थीं। टीज़र में जितेंद्र कुमार की वॉयस ओवर सुनाई देती है, जो फिल्म में गुलाब हकीम का किरदार निभा रहे हैं, जबकि महवश को नगमा के रूप में पेश किया गया है। रेमो डिसूजा ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि यह कहानी गुलाब और नगमा की मोहब्बत की है, "एक ऐसी मोहब्बत जिसकी जान कम है, लेकिन जुनून ज्यादा है। गुलाब में मोहब्बत का कीड़ा है और नगमा में कुदरत का।" यह कैप्शन फिल्म की भावनात्मक और रोमांटिक थ्रिलर शैली की झलक देता है, जिससे स्पष्ट होता है कि फिल्म केवल एक सामान्य प्रेम कहानी नहीं बल्कि टेढ़ी-मेढ़ी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पली-बढ़ी मोहब्बत पर आधारित होगी। फिल्म का निर्देशन जयेश प्रधान ने किया है और टीज़र देखने के बाद यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहानी में रोमैंस, ड्रामा और इमोशन का अनोखा मिश्रण दर्शकों को बड़े पर्दे पर बांधे रखेगा। टीज़र का संगीत और विज़ुअल इफेक्ट्स भी इस फिल्म के अनुभव को और जीवंत बनाते हैं, और दर्शकों को यह बताने में सक्षम हैं कि 'टेढ़ी है पर मेरी है' सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसमें जुनून, संवेदनशीलता और इमोशनल गहराई को प्राथमिकता दी गई है। इस नई फिल्म के साथ रेमो डिसूजा अपने निर्देशन और कोरियोग्राफी की जादूगरी को बड़े पर्दे पर फिर से साबित करने की तैयारी में हैं।

हिन्दी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान

राष्ट्रीय स्वाभिमान
पत्र व्यवहार:रफ्तार इंडिया एक्सप्रेस, 31/33 पहला महला, पत्रावाला बिल्डिंग, वजु कोटक मार्ग लिंक शहीद भगतसिंह रोड, फोर्ट, मुंबई 400001, भ्र.ध्व. क्र.:9224733113
ईमेल:rastriyaswabhimaan@gmail.com

04 मुंबई, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 महाराष्ट्र
epaper.rashtriyaswabhimaan.in
www.rashtriyaswabhimaan.com

“हम भी इंसान हैं... सरकार हमें जीने दे”-मुंबई में पारधी समाज का दर्द

मुंबई जैसे विशाल और आधुनिक महानगर के बीच, जहाँ रात की रोशनी और ऊँची इमारतें आसमान को छूती दिखाई देती हैं, वहीं एक ऐसा समुदाय है जिसकी आवाज़ वर्षों से हवा में गुम होती चली जा रही है—पारधी समुदाय। मंगलवार को मुंबई में हुए एक प्रेस वार्ता में इस समाज के लोग एकजुट होकर बैठे, और पहली बार अपने भीतर दबे हुए दर्द को इतने तीखे शब्दों में सामने रखा कि पूरा हॉल कुछ देर के लिए शांत हो गया। गीता काले की आँखों में अजीब-सी बेचैनी थी, आवाज़ काँप रही थी, पर शब्दों में हिम्मत थी। उन्होंने सवाल दागा—“क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारा केवल यही अपराध है कि हम पारधी हैं? अगर जीने का अधिकार नहीं है तो सरकार साफ कह दे हमें गोली मार दे, पर रोज़-रोज़ ये अपमान क्यों?” हॉल में बैठे कई पारधी परिवार उनके इन शब्दों के साथ रो पड़े। वे लोग मुंबई के अलग-अलग इलाकों से आए थे—विले पार्ले, बोरीवली, दहिसर,

मलाड और कई अन्य हिस्सों से। सभी का दर्द एक जैसा था, सभी की कहानी लगभग एक ही धागे से बुनी लगती थी। कोई माँ अपनी गोद में बीमार बच्चा लिए बैठी थी, कोई बुज़ुर्ग काँपते हाथों से लाठी संभाल रहा था, कोई युवा अपना भविष्य खोते हुए देख रहा था। पर सबसे ज्यादा डर बच्चों की आँखों में दिख रहा था। वे बड़े-बड़ों की बातें नहीं समझते, पर अपने टूटे घरों को ज़रूर समझ गए थे। समुदाय ने अपनी बात रखना शुरू की, और सबसे पहले बोरीवली के चिकुवाड़ी क्षेत्र की घटना सामने आई। 2 दिसंबर की सुबह जब लोग अभी जाग भी नहीं पाए थे, तभी बीएमसी और पुलिस की संयुक्त टीम उनके इलाके में पहुँची। अचानक से शोर मच गया, मशीनों की आवाज़, पुलिस की सख्ती और बच्चों की चीखें मिलकर ऐसा दृश्य बना रही थीं जैसे किसी युद्ध का मैदान हो। कुल 55 झोपड़ियाँ कुछ ही घंटों में ढहा दी गईं। दिसंबर की ठंड में, जब शरीर अंदर तक जमा देता है, तब ये परिवार खुले आसमान के नीचे खड़े देख रहे थे कि उनकी पूरी दुनिया मलबे में बदल गई है। किसी को अपने कपड़े निकालने का मौका नहीं मिला, किसी को अपनी दवाई, और कई बच्चों के स्कूल बैग अभी भी उस मलबे में दबे पड़े हैं।

कम्युनिटी से जुड़े लोगों ने बताया कि कम से कम 25 बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई अब रुक गई है। उनमें से एक पाँचवी कक्षा का बच्चा—जिसने बड़ी मेहनत से स्कूल जाना शुरू किया था—अब रोज़ अपनी माँ से यही पूछता है, “हमारा घर वापस कब बनेगा? मैं पढ़ने कब जाऊँगा?” लेकिन उसकी माँ क्या जवाब दे? मलबे की ढेर पर बैठकर किताबें नहीं पढ़ी जातीं। कुछ बच्चे तो ठंड से काँपते हुए अभी भी वहीं इधर-उधर खेलते दिखाई देते हैं, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका घर क्यों तोड़ा गया और अब वे कहाँ जाएँ।

सबसे दर्दनाक पहलू उन बीमार और बुज़ुर्ग लोगों का था, जिन्हें अपने शरीर का भार उठाना भी मुश्किल हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कैंसर पीड़ित बुज़ुर्ग को स्ट्रेचर पर लाया गया। उसके परिवार ने बताया कि डॉक्टरों ने उसे साफ और सुरक्षित जगह पर आराम करने की सलाह दी थी, पर झोपड़ी टूटने के बाद उसके पास सिर छिपाने की भी जगह नहीं बची। एक माँ अपने बीमार बच्चे को अपनी चुन्नी में लपेटे बैठी थी और कह रही थी—“हमने क्या गलती की है? हम तो बस जीना चाहते हैं।”

समुदाय ने यह भी बताया कि विडंबना यह है कि नालों की सफाई, सड़क किनारे मजदूरी और कई नगर निगम के काम इसी समुदाय के लोग वर्षों से करते आए हैं। शहर की सफाई और कई बुनियादी कामों में उनका योगदान रहा है, लेकिन जब उन्हें रहने के लिए थोड़ी-सी जगह चाहिए, तब उन्हें “अवैध” कहकर खदेड़ दिया जाता है। एक महिला ने भावुक होकर कहा—“जब काम चाहिए था, तो हम सही थे। आज रहने को कहना तो हम गलत हो गए? क्या हमारे बच्चों को सिर्फ इसलिए छत नसीब नहीं होगी क्योंकि हम पारधी हैं?”

गैस सिलेंडर चोरी के चार मामलों का बड़ा खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

पालघर। सफाला और केलवा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पिछले कुछ समय से आंगनवाड़ी केंद्रों, बंगलों और स्कूलों में ताले तोड़कर गैस सिलेंडर चोरी किए जाने की कई शिकायतें दर्ज की जा रही थीं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और चार अलग-अलग चोरी की वारदातों के पीछे एक ही गैंग का हाथ होने की पुष्टि हुई।

शिकायतों के आधार पर सफाला पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 161/2025, 162/2025 और 163/2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 305, 331(1) और 331(4) के तहत दर्ज किए गए, जबकि केलवा सागरी पुलिस स्टेशन में भी इसी प्रकरण में अपराध क्रमांक 73/2025 दर्ज किया गया था। लगातार बढ़ते इन मामलों के बाद पुलिस अधीक्षक यतिश देशमुख के मार्गदर्शन में सफाला पुलिस स्टेशन की एक विशेष टीम गठित की गई। इस कार्रवाई का समन्वय अपर पुलिस अधीक्षक विनायक नरळे तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रभा राऊत द्वारा किया गया।

विशेष टीम ने घटनास्थलों का निरीक्षण किया और तकनीकी विश्लेषण के साथ-साथ गोपनीय सूत्रों से जानकारी जुटाकर दो संदिग्धों पर संदेह बनाया। बाद में दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने इन चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अजय एकनाथ आंबात (32), निवासी बंदाटे, तालुका पालघर और चंदू रमेश वळवी (25), निवासी देवशेत, तालुका पालघर के रूप में हुई है।

आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 25 गैस सिलेंडर और एक मोटरसाइकिल सहित 1,28,000 रुपये मूल्य का चोरी किया गया सामान बरामद किया है। फिलहाल चारों मामलों की आगे की जांच सफाला पुलिस स्टेशन ही कर रहा है। कार्रवाई का संचालन सपोनि दत्ता शेलके, प्रभारी अधिकारी, सफाला पुलिस स्टेशन द्वारा किया गया, जबकि स्टेशन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी इस अभियान में शामिल रहे और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह कार्रवाई पालघर पुलिस की तत्परता और समन्वय के कारण सफल रही है तथा आगे की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

टाटा सिएरा ने बनाया नया फ्यूल-एफिशिएंसी रिकॉर्ड

मुंबईः टाटा मोटर्स की नई टाटा सिएरा ने इंदौर के नैटरैक्स ट्रैक पर 12 घंटे में 29.9 किमी/लीटर का माइलेज देकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई। पिक्सेल मोशन टीम ने वाहन को 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक लगातार चलाकर यह उपलब्धि हासिल की। सिएरा में लगा नया 1.5L हाइपेरियन पेट्रोल इंजन इसकी शानदार एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस की वजह बना। टाटा मोटर्स के सीपीओ मोहन सावरकर ने कहा कि यह रिकॉर्ड हाइपेरियन प्लेटफ़ॉर्म की क्षमता और कंपनी के उन्नत तकनीक की प्रतिबद्धता को साबित करता है।

टेस्ट के दौरान सिएरा ने 222 किमी/घंटा की टॉप स्पीड भी दर्ज की।

भारत और ब्राज़ील के बीच समुद्री सुरक्षा का नया युग एमडीएल द्वारा ऐतिहासिक नौसैनिक साझेदारी पर मुहर

मुंबई से उठती समुद्री हवाएँ इन दिनों एक नई कहानी कह रही हैं—एक ऐसी कहानी जो दो महाद्वीपों, दो लोकतांत्रिक देशों और दो मजबूत नौसेनाओं को एक अद्भुत तकनीकी बंधन में जोड़ती है। भारत के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने भारतीय नौसेना और ब्राजीलियाई नौसेना के साथ मिलकर जो रक्षा समझौता किया है, वह केवल एक MoU नहीं, बल्कि भविष्य के समुद्री सहयोग की आधारशिला है। 9 दिसंबर को ब्राजीलिया में हुए इस ऐतिहासिक दस्तखत ने हिंद महासागर और दक्षिण अटलांटिक के बीच एक नया रणनीतिक पुल खड़ा कर दिया है।

यह समझौता स्कॉर्पीन-श्रेणी की पनडुब्बियों और नौसैनिक जहाज़ों के रखरखाव को लेकर है, पर

इसके पीछे छिपी गंभीरता और महत्व इससे कहीं आगे जाता है। बीते दशक में भारत की समुद्री क्षमताएँ जितनी तेजी से विकसित हुई हैं, उसमें मझगांव डॉक की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण रही है। पी-75 प्रोजेक्ट के तहत स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण कर भारत ने न केवल आत्मनिर्भरता हासिल की, बल्कि अब तकनीकी विशेषज्ञता भी उस स्तर पर पहुँच गई है कि वह अन्य देशों के साथ मिलकर समुद्री रक्षा को नया रूप दे सकता है।

ब्राजील, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति है, लंबे समय से अपनी पनडुब्बियों और समुद्री तकनीक को उन्नत करने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में भारत का यह साझेदारी हाथ बढ़ाना द्विपक्षीय विश्वास की इतनी बड़ी मिसाल है कि इसे दोनों देशों की सामूहिक समुद्री सुरक्षा का नया अध्याय कहा जा रहा है। दोनों देशों की नौसेनाएँ अब अपने अनुभवों, तकनीकी प्रक्रियाओं और रखरखाव विशेषज्ञता को साझा करेंगी—जिससे आने वाले वर्षों में यह सहयोग और गहरा होने वाला है।

समझौते के अंतर्गत जानकारी का आदान-प्रदान केवल मशीनों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें जीवनचक्र प्रबंधन, मरम्मत की उन्नत तकनीकें, विशेष उपकरणों का संचालन, और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता जैसे अनेक पहलू शामिल हैं। सबसे रोचक पहलू यह है कि दोनों देश अपने-अपने कर्मियों को एक-दूसरे के पास भेजकर प्रशिक्षण देंगे। जब भारतीय इंजीनियर ब्राज़ील की डॉकयार्डों में जाकर अपनी विशेषज्ञता साझा करेंगे और ब्राज़ीलियाई तकनीशियन मुंबई में भारतीय प्रक्रियाओं को सीखेंगे, तो यह केवल तकनीक नहीं—दो संस्कृतियों, दो तकनीकी परंपराओं का एक अद्भुत संगम होगा।

वार्षिक तकनीकी बैठकें इस साझेदारी की रीढ़ बनेंगी, जो बारी-बारी से भारत और ब्राजील में आयोजित होंगी। इन बैठकों में प्रगति की समीक्षा, नई जरूरतों का विश्लेषण और भविष्य की योजनाओं का रोडमैप तैयार किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सहयोग केवल कागज पर दर्ज न रह जाए, बल्कि वास्तविक रूप से विकसित होता रहे।

इस MoU का एक और महत्वपूर्ण पहलू है—संयुक्त अनुसंधान और रक्षा आर एंड डी पर दिया गया असाधारण जोर। दुनिया की समुद्री तकनीकें जिस तेजी से बदल रही हैं, उसमें पनडुब्बियों, हथियार प्रणालियों, मशीनरी और प्रोपल्शन सिस्टम में नवाचार अत्यंत आवश्यक हो गया है। भारत और ब्राज़ील अब इस क्षेत्र में साथ-साथ शोध करेंगे, नई तकनीकों का विकास करेंगे और समुद्री सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए मॉडलों पर काम करेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि इस पूरे सहयोग में कोई वित्तीय लेनदेन नहीं होगा; प्रत्येक देश अपनी लागत स्वयं वहन करेगा—जो यह दर्शाता है कि यह साझेदारी व्यापारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक विश्वास पर आधारित है।

यह समझौता दस वर्षों के लिए लागू रहेगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह अवधि केवल औपचारिकता है। इस स्तर का सहयोग अक्सर दशक दर दशक आगे बढ़ता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए नई विरासत छोड़ता है।

डिजी यात्रा उपयोग 1.9 करोड़ पार, अब अंतरराष्ट्रीय विस्तार की तैयारी

मुंबई। डिजी यात्रा प्लेटफ़ॉर्म को अब तक 1.9 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं ने डाउनलोड किया है और देश के 24 हवाई अड्डों पर करीब 30% यात्री इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे 7.7 करोड़ से ज्यादा यात्राएँ आसान और संपर्करहित तरीके से पूरी की जा चुकी हैं। प्लेटफ़ॉर्म का लक्ष्य है कि 2028 तक 80% हवाई यात्री डिजी यात्रा अपनाएं और 2026 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पासपोर्ट-आधारित डिजिटल पहचान के साथ इंटरऑपरेबल सिस्टम शुरू किया जा सके।डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए इसका बीटा संस्करण छह भारतीय भाषाओं में शुरू किया गया है, जिसे आगे चलकर सभी 22 आधिकारिक भाषाओं तक बढ़ाया जाएगा, जबकि एयरलाइंस और ट्रैवल ऐप्स के साथ इंटीग्रेशन से सीधे बोर्डिंग पास शेयरिंग और हवाई अड्डों पर तेज़ प्रोसेस संभव हो रही है। भविष्य में आवश्यक मंजूरियों के बाद इसे होटल चेक-इन, संग्रहालयों और पर्यटन स्थलों पर भी फेस-बेस्ड सुरक्षित व त्वरित एंट्री के लिए उपयोग करने की योजना है।

पोको C85 5G लॉन्चः 12 हजार से कम में पावरफुल बैटरी और बड़ा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन

मुंबई। पोको ने भारत में नया स्मार्टफोन POCO C85 5G लॉन्च किया है, जिसे खास तौर पर ऐसे युवाओं के लिए पेश किया गया है जो बजट सेगमेंट में दमदार बैटरी, बड़ा डिस्प्ले और स्टाइलिश लुक चाहते हैं। यह फोन 12 हजार रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में पेश किया गया है और कंपनी इसे “पावर, परफॉर्मेंस और वैल्यू” का कॉम्बो बता रही है।फोन में 6000mAh बैटरी दी गई है, जो कंपनी के अनुसार दो दिन से अधिक का बैकअप दे सकती है, साथ ही 33W फास्ट चार्जिंग से करीब 28 मिनट में 50% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि 10W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग की मदद से यह अन्य मोबाइल, TWS या स्मार्टवॉच के लिए पावर बैंक की तरह भी काम कर सकता है। डिज़ाइन की बात करें तो C85 5G स्लिम 7.99mm प्रोफ़ाइल, क्वाड-कर्व्ड बैक और प्रीमियम डुअल-टोन फ़िनिश के साथ मिस्टिक पर्पल, स्प्रिंग ग्रीन और पावर ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध रहेगा।डिस्प्ले के तौर पर इसमें सेगमेंट का सबसे बड़ा 6.9-इंच HD+ स्क्रीन दिया गया है, जिसमें 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर गेमिंग अनुभव का दावा किया

गया है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 16GB तक टर्बो RAM, एंड्रॉयड 15 आधारित HyperOS 2.2, IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस, पीछे की तरफ 50MP AI डुअल रियर कैमरा और फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा दिया गया है।कंपनी के जीटीएम हेड अंकित सिंह और मार्केटिंग हेड केन शेखर के अनुसार, POCO C85 5G को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह लंबी बैटरी लाइफ, बड़े डिस्प्ले, गेमिंग, बिंज-वॉचिंग और मल्टीटास्किंग जैसी जरूरतों को बजट सेगमेंट में बिना समझौते के पूरा कर सके और यूजर्स को रोजमर्रा के उपयोग में ज्यादा भरोसा और कंट्रोल का अनुभव दे।

तपोवन बचाने की उम्मीद जगीः मुख्यमंत्री ऑफिस ने पर्यावरणविद डॉ. सिनकर की आपत्ति पर तुरंत कार्रवाई शुरू की

ठाणे। नासिक के तपोवन क्षेत्र में कुंभ मेले की तैयारियों के नाम पर प्रस्तावित पेड़ कटाई के खिलाफ पर्यावरणविद डॉ. प्रशांत रवींद्र सिनकर द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिए गए विस्तृत मेमोरेंडम पर मुख्यमंत्री ऑफिस ने तुरंत संज्ञान लिया है।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ऑफिस ने यह प्रस्ताव तत्काल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजते हुए जरूरी कार्रवाई करने और पूरे मामले को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से दोबारा जांचने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

तपोवन को नासिक के रफेफड़ेश के रूप में जाना जाता है। यहां बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई

का प्रस्ताव सामने आने के बाद नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों में भारी आक्रोश फैल गया था। डॉ. सिनकर ने मेमोरेंडम में स्पष्ट कहा कि—“कुंभ मेला पवित्र है, परंतु इसकी तैयारी प्रकृति की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।” उन्होंने कई वैकल्पिक उपायों की सूची भी सरकार को सौंपी।

सरकार की तत्परता के बाद नासिक में पर्यावरणविदों और स्थानीय नागरिकों में राहत का माहौल है। उम्मीद जताई जा रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पुनः समीक्षा के बाद ऐसा निर्णय आएगा जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कायम करेगा। डॉ. प्रशांत सिनकर ने कहा कि सरकार, नागरिकों और विशेषज्ञों की संयुक्त कोशिशें ही तपोवन की हरियाली को बचाने में असली भूमिका निभाएंगी।

ठाणे में तंबाकू विरोधी जागरूकता अभियान को जोरदार प्रतिसाद, स्टूडेंट्स ने ली नशा-मुक्ति की शपथ

ठाणे। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा युवाओं को तंबाकू की लत से दूर रखने के लिए चलाया जा रहा एंटी-टोबैको कैंपेन ठाणे में बेहद सफल साबित हो रहा है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम और जिला सिविल अस्पताल के संयुक्त प्रयास से गांधी नगर के नवजीवन प्राइमरी स्कूल और चेकनाका के माजगांव नाइट स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कैंपेन में स्टूडेंट्स को तंबाकू के नुकसान, लत से जुड़ी समस्याएं और कम उम्र में

नशा छोड़ने के तरीकों के बारे में आसान भाषा में समझाया गया। शुरुआत एंटी-टोबैको डॉक्यूमेंट्री से हुई, जिसने बच्चों में तुरंत जागरूकता बढ़ाई। जिला सिविल अस्पताल की डेंटल सर्जन डॉ. अर्चना पवार ने स्टूडेंट्स व पेरेंट्स से संवाद करते हुए बताया कि तंबाकू दांतों, मुंह और सांस से जुड़ी बीमारियों का बड़ा कारण है और एक छोटी सी आदत पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इस अभियान में नवजीवन विद्यालय, मझगांव रात्र स्कूल, मासूम सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं ने आयोजन, उपस्थिति और जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेरेंट्स और टीचर्स ने भी ‘तंबाकू-फ्री स्कूल’ और ‘तंबाकू-फ्री कैंपस’ पहल को आगे बढ़ाने का संकल्प जताया।

कार्यक्रम के अंत में सभी स्टूडेंट्स ने शपथ ली “हम तंबाकू-फ्री रहेंगे” और नशा-मुक्त समाज बनाने का वादा किया। डॉ. कैलाश पवार, जिला सिविल सर्जन ठाणे ने कहा कि तंबाकू विरोधी अभियान सिर्फ एक कैंपेन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की जान बचाने की लड़ाई है।”